International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 43-52

राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति का विश्लेष्णात्मक अध्ययनः (वर्ष 2018–19 से 2022–23)

Murli Dhar Meena*
Prof. (Dr.) Prakash Sharma**

सार

लोकतंत्र में वित्तीय अनुशासन का मूल सिद्धांत है की सभी धन प्राप्तियों एवं व्ययों का बजट बनाया जाना चाहिए एवं स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकार के वार्षिक आय एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण उस सरकार का बजट कहलाता है, यह आरम्भ हो रहे वित्तीय वर्ष में सरकार को होने वाली संभावित आय तथा संभावित व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सरकार को वर्ष के दौरान होने वाली वास्तविक प्राप्तियो एवं व्ययों के आधार पर सरकार के लेखे तेयार किये जाते है। राज्य सरकार के गत वर्षो के लेखो से सरकार के राजस्व, बजट एवं राजकोषीय स्थिति की जानकारी मिलती है। प्रस्तुत शोध "राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति का विश्लेष्णात्मक अध्ययन" में राजस्व, बजट एवं राजकोषीय आधिक्य–घाटा तथा इनके विभिन्न घटकों का वर्ष 2018–19 से 2022–23 (पांच वर्ष) के मध्य विश्लेष्णात्मक अध्ययन एवं प्रवत्ति विश्लेषण किया गया है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करने पर इनकी वर्षवार प्राप्तियों एवं व्ययों की एक प्रवत्ति स्पष्ट होती है। यह शोध राज्य सरकार के राजकोषीय स्थिति में वर्षवार होने वाले परिवर्तनों एवं राजकोष के वित्तीय प्रबंधन की व्याख्या करता है तथा आवश्यक सुझाव प्रदान करता है। यह शोध इस विषय पर उपलब्ध शोध अध्ययनों की समीक्षा करके किया गया है। लेखक को आशा है की पेपर के निष्कर्ष भारत में राज्य सरकारों के लिये के लिए बजट निर्माण एवं राजकोष के वित्तीय प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण सहयोगी साबित होंगे।

शब्दकोशः *बजट, राजस्व आय–व्यय, पूंजीगत आय–व्यय, राजकोषीय आधिक्य–घाटा एवं वित्तीय प्रबंधन।*

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। यह देश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। इसके पूर्वी भाग में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश य दक्षिण–पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण–पश्चिम में गुजरात स्थित है। पश्चिम में राजस्थान की पाकिस्तान से लगती हुई सुदीर्घ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 'राजस्थान' शब्द का प्रथम बार प्रयोग प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड की पुस्तक "एनाल्स एंड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान" (1829, लन्दन) में किया गया। 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिला है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक द्रष्टि राज्य को चार भागों (i) पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, (ii) अरावली पहाड़ी प्रदेश, (iii) पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा (iv) दक्षिणी–पूर्वी पठार में विभाजित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2022 में राजस्थान की जनसंख्या

* Research Scholar, Assistant Professor of Accountancy and Business Statistics, Shri Govind Guru Government College, Banswara, Rajasthan, India.
** Supervisor & Head, Department of Accountancy and Business Statistics, University of Rajasthan, Rajasthan, India.

लगभग 8.01 करोड़ अनुमानित की है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। राजस्थान में 75.1 प्रतिशत ग्रामीण आबादी एवं 24.9 प्रतिशत शहरी आबादी है। राजस्थान में लिंगानुपात 928 है एवं बच्चो का लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष आयु वर्ग) 888 है। राजस्थान में साक्षरता की दर 66.1 प्रतिशत है, पुरुष साक्षरता 79.2 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 52.1 प्रतिशत है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः 17.8 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5 प्रतिशत है।

अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध कार्यप्रणाली

उपरोक्त अध्ययन का उद्देश्य राज्य के आर्थिक वातावरण के वर्तमान परिद्रश्य एवं आर्थिक विकास के मुख्य सूचकों का अध्ययन करना है। राज्य के विभिन्न वर्षो के आय–व्यय एवं राजकोषीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सुझाव प्रदान करना है। वर्तमान शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेष्णात्मक प्रकृति का हैं। शोधकर्ता ने द्वितीयक डेटा विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया हैं इसमें भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की वार्षिक बजट रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, सरकारी दस्तावेज एवं अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित स्त्रोतों से डेटा का संग्रहण करना एवं उनका विश्लेषण करना सम्मिलित है। प्रस्तुत शोध "राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति का विश्लेष्णात्मक अध्ययन" में राजस्व, बजट एवं राजकोषीय आधिक्य–घाटा तथा इनके विभिन्न घटकों का वर्ष 2018–19 से 2022–23 (पांच वर्ष) के मध्य विश्लेष्णात्मक अध्ययन एवं प्रवत्ति विश्लेषण किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

गुप्ता एस. , सिंह के. (2016) के अनुसार भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा पहली बार 1991 में पेश की गई थी। राजकोषीय घाटे को राजस्व घाटे एवं पूंजीगत व्यय (ऋण और अन्य प्राप्तियों की वसूली को घटाकर) के योग के रूप में परिभाषित किया गया था। तब से राजकोषीय घाटा के आधार पर ही भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापा जाता है। अध्ययन में लेखक ने 1980–81 के बाद से भारत की राजकोषीय नीति में बड़े बदलावों 1991 के देश के भुगतान संकट के संतुलन, आर्थिक उदारीकरण और उच्च विकास अवधि, 2003 में एफआरबीएम अधिनियम की शुरुआत, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समायोजन और हाल ही में संकट के बाद राजकोषीय समेकन के रास्ते पर लौटने के राजकोषीय नीति पर होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया है। लेखक के अनुसार 1980–81 से 2002–03 के दौरान घाटा अधारणीय स्तर तक बढ़ गया और सरकार को आर्थिक सुधारों को लागू करने और अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई । वर्ष 2003–04 से सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में धीरे–धीरे कमी सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय नीति में सुधार किए हैं ।

भारद्वाज वि. (2009) के अनुसार राज्य सरकार का मूल उद्देश्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है न कि लाभ अधिकतम करना। लेखक के शोध अध्ययन अवधी में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से प्राप्त होने वाली प्राप्तियो की तुलना में वृद्धी दर कम है एवं राज्य के स्वयं के करो से आय में भी केंद्र सरकार से केन्द्रीय करो में हिस्से के रूप में मिलने वाली प्राप्तियो से वृद्धी दर कम है शोधार्थी के अनुसार शोध अवधी के दौरान लोक ऋण की स्थिति सरकार के नियंत्रण में है एवं राज्य के ऋणों की संचयी स्थिति में भी सुधार हुआ है। राज्य में 2005 से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक लागू किया गया है, जिसके उपरांत राज्य का राजस्व घाटा कम हुआ है एवं राज्य को राजस्व आधिक्य वाले राज्यों में जाना जाने लगा है। वर्ष 2007–08 में राज्य का राजकोषीय घाटा बहुत ही कम 0.19 प्रतिशत रहा है। शोधार्थी ने राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी एवं सराहनीय मानी है।

जगदीश पी. बी. (2019) ने राज्य की सरकारी वित्तीय प्रणाली में ई–गवर्नेंस पर किये गए अपने शोध अध्ययन में बताया है कि राज्य की करो से आय में 72 प्रतिशत विक्रय एवं व्यापार पर लगने वाले करो से, 10 प्रतिशत अन्य करो से एवं 8.7 प्रतिशत स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का हिस्सा है। राज्य योजना स्कीमों के लिए भारत सरकार से लगभग 60 प्रतिशत सहायता अनुदान प्राप्त होता है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान में से लगभग 25 प्रतिशत गैर–योजना सहायता अनुदान होता है एवं लगभग 14 प्रतिशत केंद्र

सरकार की योजनाओ के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य स्त्रोत ऋण एवं अग्रिम की वसूली है। शोधार्थी ने गतिविधि आधारित व्ययों का विश्लेषण करने पर पाया की शोध अवधी के दौरान राज्य द्वारा लगभग 40 प्रतिशत राशी सामाजिक गतिविधियों के लिए आवंटित की है। सामान्य एवं आर्थिक सेवाओ के लिए औसतन 30 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

मोहंती आर. के. (2012) के अध्ययन का मूल उद्देश्य 1970–71 से 2011–12 तक की समयावधि को कवर करके भारत में राजकोषीय घाटे और आर्थिक विकास के बीच अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों संबंधों की जांच करना है। पेपर के निष्कर्ष बताते हैं कि लंबे समय में राजकोषीय घाटे और आर्थिक विकास के बीच एक नकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध है। अध्ययन के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि आर्थिक विकास पर पश्च–सुधार राजकोषीय घाटे का नकारात्मक प्रभाव सुधार–पूर्व के राजकोषीय घाटे के प्रभाव से अधिक है।

बर्की जी. एस. (2020) अनुसार सुशासन की सुविधा देने वाली सरकार के मामले में अच्छी योजना और प्रबंधन हमेशा आधी लड़ाई जीत जाता है। शासन द्वारा वर्ष में एक बार योजना एवं प्रबंधन बजट के रूप में किया जाता है। उत्पन्न आय के आधार पर व्यय नियंत्रण करने तथा भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए आवश्यक और विकास प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन के लिए प्राथमिकताओं की स्थापना करने में बजट महत्वपूर्ण है ।

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का मापन विभिन्न आर्थिक संकेतकों सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) एवं प्रति व्यक्ति आय (PCI) आदि द्वारा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022–23, राजस्थान सरकार अनुसार, राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कहा जाता है एवं सकल घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) का अनुमान प्राप्त किया जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रति व्यक्ति आय (PCI) आंकलित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगो के जीवन स्तर एवं सम्पन्नता की सूचक है। राजस्थान राज्य का प्रचलित कीमतों पर एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) एवं प्रति व्यक्ति आय (PCI) तालिका 1 तथा चित्र 1 एवं चित्र 2 में दर्शाए गए है ।

तालिका 1: राजस्थान राज्य का वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product)	₹ करोड					
	(v) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		643278	676785	663515	738922	799449
	(c) प्रचलित मूल्यों पर		911519	998679	1019442	1218193	1413620
2.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product)	₹ करोड					
	(v) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		568452	596689	576789	642668	694771
	(c) प्रचलित मूल्यों पर		819185	898116	907861	1084845	1259527
3.	प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)	₹					
	(v) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		73975	76643	73140	80545	86134
	(c) प्रचलित मूल्यों पर		106604	115360	115122	135962	

टिप्पणीः वर्ष 2020–21–संशोधित अनुमान II, वर्ष 2021.22. संशोधित अनुमान । एवं वर्ष 2022–23– अग्रिम अनुमान (अ.)
स्त्रोत–आर्थिक समीक्षा 2022–23, राजस्थान सरकार

चित्र–1 राजस्थान राज्य का वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) एवं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) प्रचलित कीमतों पर एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर (₹ करोड़)

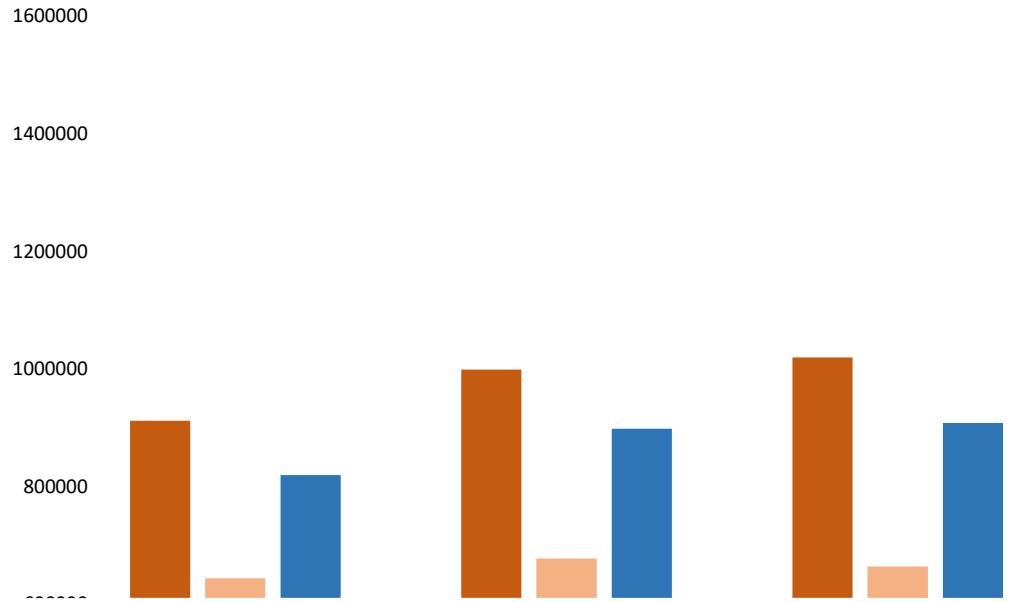

चित्र–2 राजस्थान राज्य की वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की प्रति व्यक्ति आय (PCI) प्रचलित कीमतों पर एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर (₹)

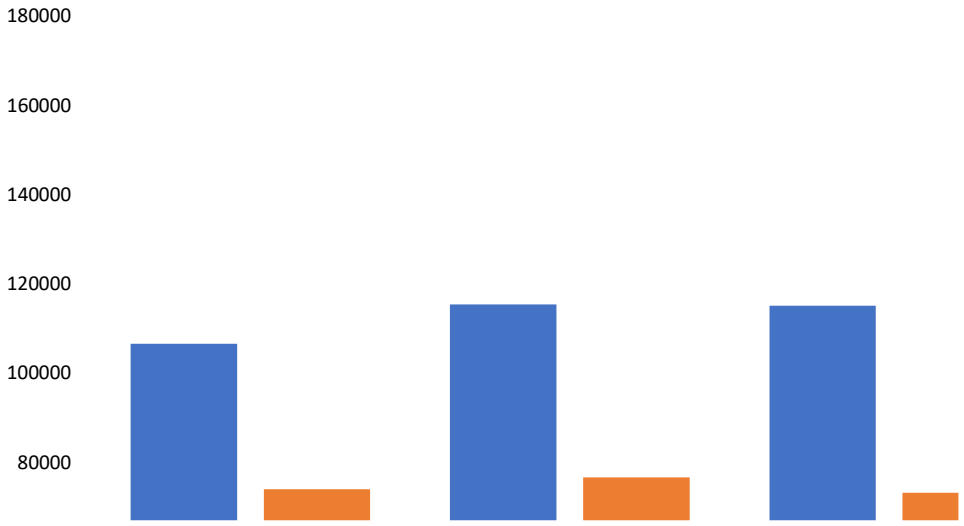

वर्ष 2018–19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) प्रचलित कीमतों पर 9,11,519 करोड एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 6,43,278 करोड था, जो की वर्ष 2022–23 में प्रचलित कीमतों पर 14,13,620 करोड एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 7,99,449 करोड हो गया है। उक्त पांच वर्षो की अवधी के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 55.08 प्रतिशत एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 24.28 प्रतिशत की बढोतरी हुई है । इसी प्रकार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) जो की वर्ष 2018–19 के दौरान प्रचलित कीमतों

पर 8,19,185 करोड एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 5,68,452 करोड था, वर्ष 2022–23 में प्रचलित कीमतों पर 12,59,527 करोड एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 6,94,771 करोड हो गया है । वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधी के दौरान शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 53.75 प्रतिशत एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 22.22 प्रतिशत की बढोतरी हुई है ।

वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्ति आय (PCI) प्रचलित कीमतों पर ₹ 1,06,604 एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर ₹ 73,975 थी, जो की वर्ष 2022–23 में बढकर प्रचलित कीमतों पर ₹ 1,56,149 एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर ₹ 86,134 हो गईं है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में उक्त पांच वर्षो की अवधी के दौरान प्रचलित कीमतों पर 46.48 प्रतिशत एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर 16.44 प्रतिशत की वृद्धी हुई है।

आय–व्ययक एक दृष्टि में

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आय–व्ययक एक दृष्टि में (BUDGET AT A GLANCE) वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25 अनुसार शोध अवधी के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है

तालिका 2: राजस्थान की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाली मदों का विवरण वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 तक (₹ लाख)

क्र .सं	विवरण (Particulars)	लेखे (Accounts) 2018-19	लेखे (Accounts) 2019-20	लेखे (Accounts) 2020-21	लेखे (Accounts) 2021-22	लेखे (Accounts) 2022-23
1	राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)	13787302.02	14011380.71	13430788.25	18392005.27	19498793.02
2	पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)	6648490.46	7347604.81	10070392.92	10751838.65	17694392.80
3	कुल प्राप्तियां (Total Receipts) (1+2)	20435792.48	21358985.52	23501181.17	29143843.92	37193185.82
4	राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	16677318.50	17648510.42	17830940.74	20979000.97	22647929.34
5	पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)	3766609.55	3700591.51	5678448.77	8140101.48	14571066.45
6	कुल व्यय (Total Expenditure) (4+5)	20443928.05	21349101.93	23509389.51	29119102.45	37218995.79
7	राजस्व आधिक्य (+) ⁄ घाटा (-) (Revenue Surplus) (+) / Deficit (-) (1-4)	- 2890016.48	-3637129.71	-4400152.49	-2586995.70	-3149136.32
8	बजट आधिक्य (+) ⁄ घाटा (-) Budgetary Surplus (+)/ Deficit (-) (3-6)	-8135.57	9883.59	-8208.34	24741.47	-25809.97
9	राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	3447292.11	3765435.86	5937542.43	4823778.05	5102860.87
10	प्रारम्भिक आधिक्य (+) ⁄ घाटा (-) (Primary Surplus) (+)/ Deficit (-)	-1277772.32	-1401108.93	-3417361.20	-2013731.93	-2042673.07

स्त्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आय–व्ययक एक दृष्टि में वर्ष 2020–21 से 2024–25

राज्य सरकार की पांच वर्षो की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय
(Revenue Receipts and Expenditure) (₹ लाख)

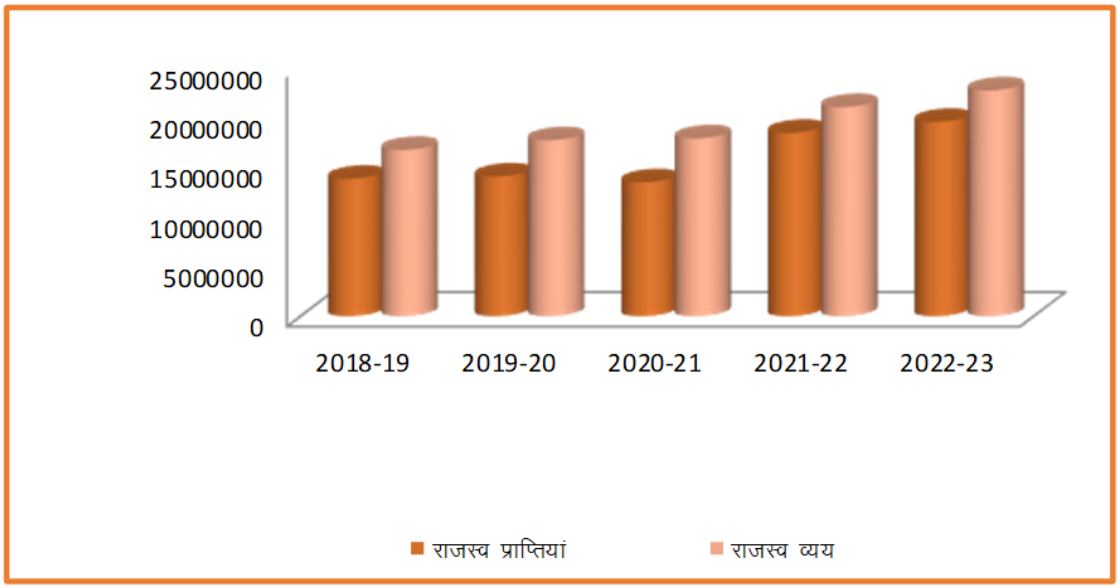

चित्र 3

राज्य सरकार की पांच वर्षो की पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय
(Revenue Receipts and Expenditure) (₹ लाख)

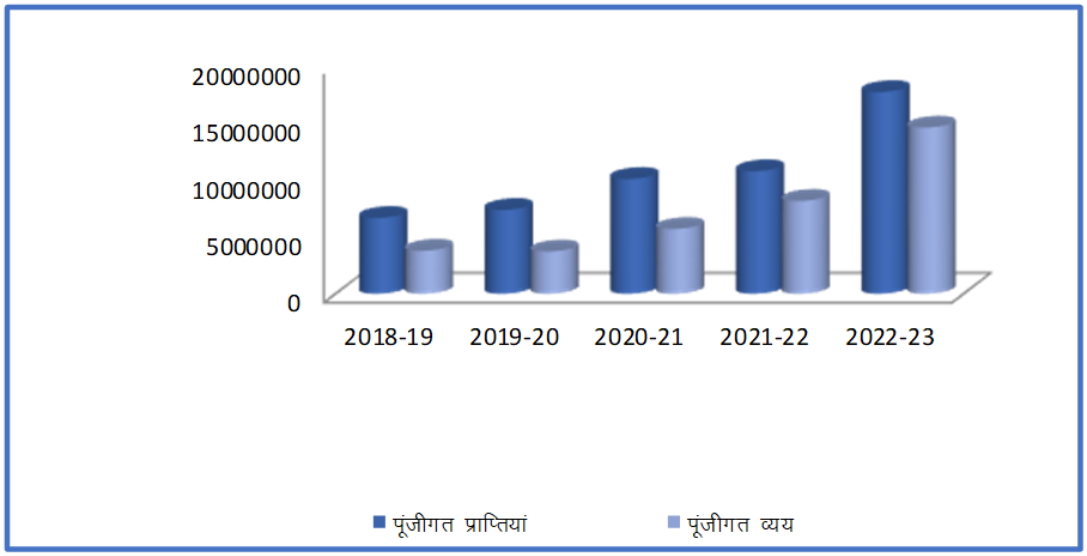

चित्र 4

राज्य सरकार की पांच वर्षो की राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है की वर्ष 2018–19 में राशि 137873.02 करोड़ की राजस्व प्राप्तिया थी जो की वर्ष 2022–23 में बढकर राशि 194987.93 करोड़ हो गयी है इनमे प्रति वर्ष बढोतरी का रुझान प्रदर्शित होता है परन्तु वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण इनमे कमी दर्ज की गयी है। इसी प्रकार राज्य की पूंजीगत प्राप्तिया वर्ष 2018–19

में राशि 66484.90 करोड़ की थी जो की वर्ष 2022–23 में बढकर राशि 176943.92 करोड़ हो गयी है इनमे भी प्रति वर्ष बढोतरी का रुझान प्रदर्शित होता है। राज्य सरकार की पांच वर्षो की राजस्व प्राप्तियों को चित्र 3 में एवं पूंजीगत प्राप्तियों को चित्र 4 में प्रदर्शित किया गया है। राज्य सरकार के पांच वर्षो के राजस्व व्ययों एवं पूंजीगत व्ययों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है की वर्ष 2018–19 में राशि 166773.18 करोड़ के राजस्व व्यय किये गए एवं 37666.09 करोड़ के पूंजीगत व्यय किये गए है, जो की वर्ष 2022–23 में बढकर राशि 226479.29 करोड़ के राजस्व व्यय एवं 145710.66 करोड़ के पूंजीगत व्यय हो गए है। राज्य के राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में प्रति वर्ष बढोतरी दर्ज की गयी है। शोध अवधी वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व व्ययों को चित्र 3 में एवं पूंजीगत व्ययों को चित्र 4 में प्रदर्शित किया गया है।

राज्य सरकार के शोध अवधी वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान प्रति वर्ष राजस्व आधिक्य/घाटा एवं बजट आधिक्य /घाटा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर राज्य की वित्तीय स्थिति की आवश्यक जानकारी मिलती है। राजस्व आधिक्य/घाटा की गणना राज्य की राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्ययों को घटाकर की गयी है एवं बजट आधिक्य/घाटा की गणना राज्य की कुल प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत) में से कुल व्ययों (राजस्व एवं पूंजीगत) को घटाकर की गयी है। राज्य सरकार का राजस्व घाटा शोध अवधी वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान क्रमशः (–)28900.16 करोड़, (–)36371.29 करोड, (–)44001.52 करोड, (–)25869.95 करोड एवं (–)31491.36 करोड का दर्ज किया गया है । राज्य के राजस्व घाटा में शोध अवधी के दौरान बढोतरी का चलन पाया गया है, इसमें वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2022–23 में 8.97 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के राजस्व घाटा को चित्र 5 में प्रदर्शित किया गया है।

राज्य सरकार का बजट आधिक्य/घाटा शोध अवधी वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान क्रमशः (–)81.35 करोड़, .()98.83 करोड, (–)82.08 करोड, .()247.41 करोड एवं (–)258.09 करोड का दर्ज किया गया है । शोध अवधी के अंतर्गत वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2021–22 में बजट आधिक्य की स्थिति भी पायी गयी है, बजट घाटा पांच वर्षो के दौरान वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2022–23 में (–)81.35 करोड से बढकर (–)258.09 करोड हो गया है, इसमें 217 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार का बजट आधिक्य/घाटा को चित्र 6 में प्रदर्शित किया गया है।

राज्य सरकार का पांच वर्षो की राजस्व आधिक्य (+) /घाटा (-)

Revenue Surplus (+) / Deficit (-) (₹ लाख)

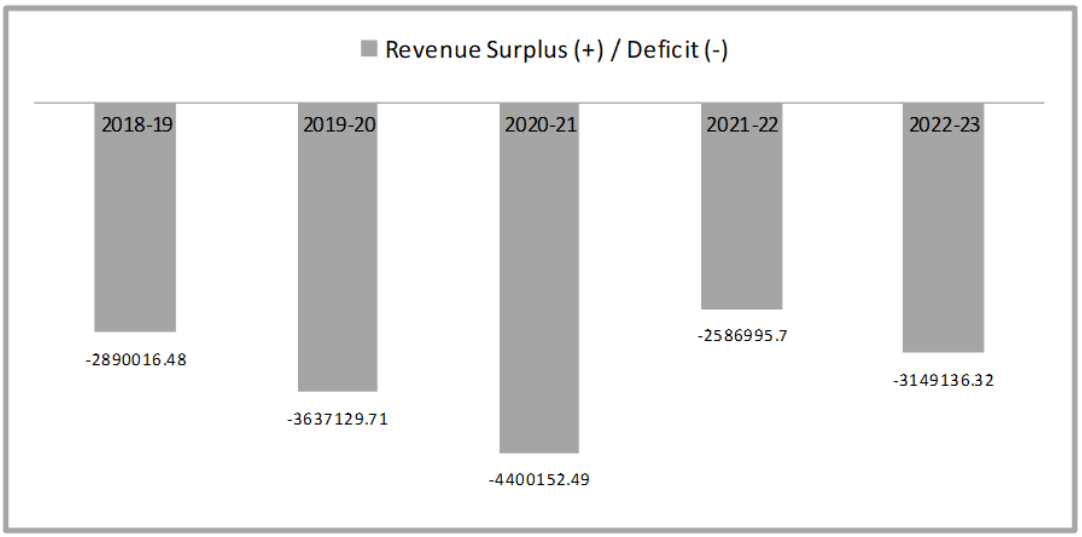

चित्र 5

राज्य सरकार का पांच वर्षो की बजट आधिक्य (+)/घाटा (-)

Budgetary Surplus (+)/ Deficit (-) (₹ लाख)

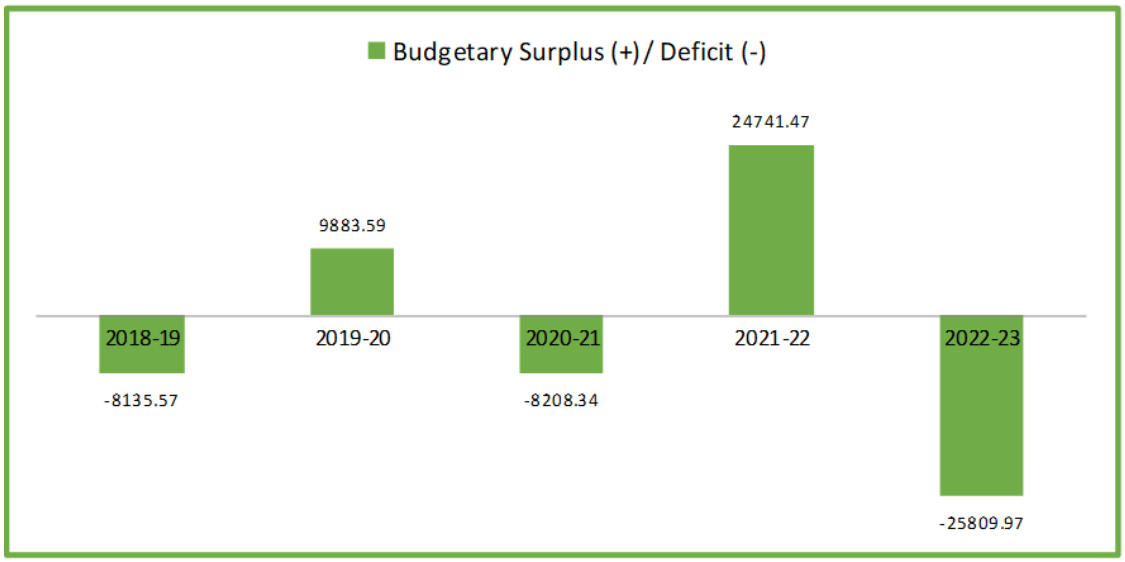

चित्र 6

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा शोध अवधी वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान क्रमशः 34492.92 करोड़, 37654.35 करोड, 59375.42 करोड, 48237.78 करोड एवं 51028.60 करोड दर्ज किया गया है । राज्य के राजकोषीय घाटा में शोध अवधी के दौरान बढोतरी का चलन पाया गया है, इसमें इनमें वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2022–23 में 47.94 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटा को चित्र 7 में प्रदर्शित किया गया है।

(₹ लाख)

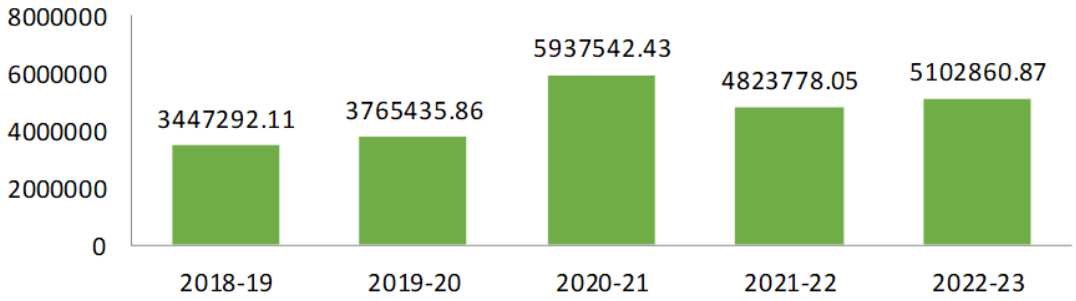

चित्र 7: राज्य सरकार का पांच वर्षो का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आय–व्ययक एक दृष्टि में 2024.25 अनुसार राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाले वित्त में सर्वाधिक 46.92 प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केन्द्रीय ऋण, ऋणों की वसूली, विविध पूंजीगत प्राप्तियां एवं आकस्मिकता निधि का है। 15.10 प्रतिशत केन्द्रीय करों में हिस्साए, 11.46 प्रतिशत राज्य वस्तु एवं सेवा कर, 7.54 प्रतिशत केन्द्रीय सहायताए 5.96 प्रतिशत बिक्री कर, 4.66 प्रतिशत कर–भिन्न राजस्व, 3.51 प्रतिशत राज्य उत्पाद शुल्क तथा 4.85 प्रतिशत अन्य करो से प्राप्त होता है।

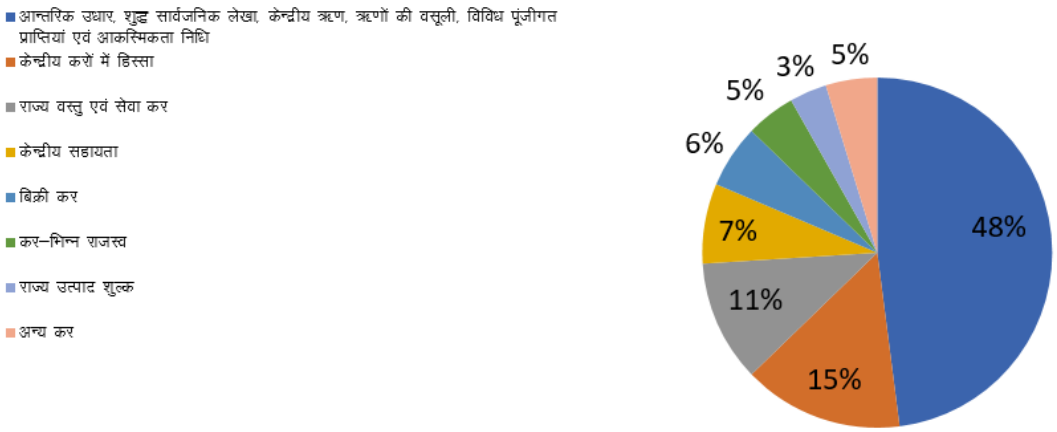

चित्र 8: राज्य को प्राप्त होने वाले वित्त में विभिन्न स्त्रोतों की हिस्सेदारी

राजस्थान राज्य द्वारा व्यय किये जाने वाले वित्त में सर्वाधिक 50.73 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय (ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त) का है। 33.02 प्रतिशत आन्तरिक व केन्द्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान एवं आकस्मिकता निधि का विनियोग, 8.92 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय, 7.28 प्रतिशत ब्याज की अदायगी तथा 0.05 प्रतिशत ऋण एवं अग्रिम के भुगतान में खर्च होता है।

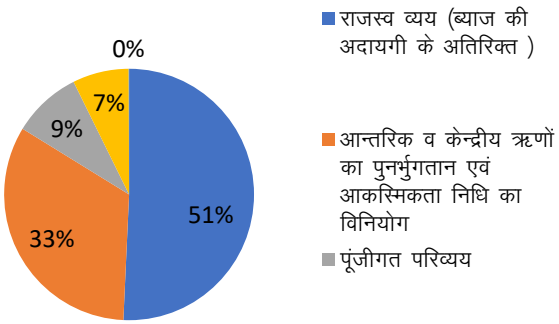

चित्र 9: राज्य द्वारा व्यय किये जाने वाले वित्त में विभिन्न स्त्रोतों की हिस्सेदारी

निष्कर्ष एवं सुझाव

वर्तमान आर्थिक परिद्रश्य में किसी भी सरकार की सफलता उसकी मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर करती है। सरकारी प्रणाली में आधुनिक वित्तीय प्रबंधन की तकनीकें पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को अपने बजटिंग प्रणाली में नवीन तकनीको जैसे कि जीरो–आधारित बजटिंग और प्रदर्शन–आधारित बजटिंग आदि को शामिल करना चाहिए, जो धन का वितरण प्राथमिकताओं और मापनीय परिणामों के आधार पर करती हैं। राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत) में शोध अवधी के दौरान प्रति वर्ष बढोतरी का चलन प्रदर्शित हुआ है। राज्य की कुल प्राप्तिया वर्ष 2018–19 में राशि 204357.92 करोड़ की थी जो की वर्ष 2022–23 में बढकर राशि 371931.85 करोड़ हो गयी है, इनमें वर्ष 2018–19 की तुलना में 82 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। राज्य की कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक 46.92 प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केन्द्रीय ऋण, ऋणों की वसूली, विविध पूंजीगत प्राप्तियां

एवं आकस्मिकता निधि का है। 15.10 प्रतिशत केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं 11.46 प्रतिशत राज्य वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा है। राज्य की कुल प्राप्तियों में कर–भिन्न राजस्व का हिस्सा 4.66 प्रतिशत है। राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य को ऋणों एवं केंद्रीय सहायता पर निर्भरता कम करते हुए अपने स्वयं के राजस्व स्त्रोत उत्पन्न करने चाहिए एवं सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों तथा पंचायती राज निकायों, स्वायतशासी संस्थाओ को अपना राजस्व बढाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा शोध अवधी वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान क्रमशः 34492.92 करोड़, 37654.35 करोड, 59375.42 करोड, 48237.78 करोड एवं 51028.60 करोड दर्ज किया गया है, इनमें वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2022–23 में 47.94 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। राज्य सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने के सार्थक प्रयास करना चाहिए, राजकोषीय घाटा राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है।

राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं अपनी वित्तीय नीतियों के समीक्षित और अनुकूलित करने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बजट में पारदर्शिता और सामंजस्य बनाये रखना, वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन रखना, राजस्व संकलन में सुधार के प्रयास करना, वित्तीय प्रबंधन में नवीन तकनीकी प्रणालियों का उपयोग आदि प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर किये जाने चाहिए अध्ययन के निष्कर्ष एवं सुझाव भारत में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को समझने एवं उनमे सुधार करने के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हों सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Barki, G. S. (2020). Assessment of Union Budget 2020-21 – A Study, Research Review International Journal of Multidisciplinary. Vol. 05, Issue-02, February-2020.
2. Bharadwaj, V. (2009). Financial Management of Chhattisgarh Government: Period 2002-2006.
3. Gupta, S., & Singh, K. (2016). Fiscal Deficit and its Trends in India. International Journal of Business and Management Invention, ISSN: 2319-801X, Vol. 5 Issue 11, November 2016, PP 63-75.
4. Jagdish, P.B. (2019). A Study of E-Governance in Government Financial System of The Gujrat State.
5. Khemani, S. (2002). Federal Politics and Budget Deficits: Evidence from the States of India. World Bank-Development Research Group, World Bank Policy Research Working Paper 2915, October 2002.
6. Mohanty, R.K. (2012). Fiscal deficit-economic growth nexus in india: A cointegration analysis. Center for Economic Studies & Planning, School of Social Sciences Jawaharlal Nehru University,2012.
7. Nazeem, S.T. (2021). Management of Government Budget in India: A Study with Special Reference to The Government of Kerala.
8. Rathod, N. (2015). An Analytical Study of Government Budget and Its Impact on Growth and Development of Chhattisgarh State.

❖◆❖